



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 18, 1997 (आश्विन 26, 1919)
No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 18, 1997 (ASVINA 26, 1919)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय में जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों में संबंधित अधिसूचनाएं	पृष्ठ 665	भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपलब्धियां भी शामिल हैं) के हिस्से अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	पृष्ठ *
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकांशियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	961	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	5	भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संच लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	907
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकांशियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1559	भाग III—खण्ड 2—सेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	1451
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड 3—मुख्य मामलों के प्राधिकार के अधीन प्रस्ताव द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक नितियों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	3389
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	339
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सारोश स्वरूप के आदेश और उपलब्धियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को बताने वाला अनुपूरक	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*		

*आंकड़ प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	PAGE		PAGE
PART I—SECTION 1 —Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	665	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii) —Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 of Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders, (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2 —Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	961	PART II—SECTION 4 —Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 3 —Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	5	PART III—SECTION 1 —Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	907
PART I—SECTION 4 —Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1559	PART III—SECTION 2 —Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	1451
PART II—SECTION 1 —Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3 —Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 1-A —Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 4 —Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3389
PART II—SECTION 2 —Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART IV —Advertisements and Notices issued by private individuals and private Bodies	339
PART II—SECTION 2—SUB-SECTION (i) —General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART V —Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc., both in English and Hindi	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii) —Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)			

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

रक्षा मंत्रालय

(डाक विभाग)

हाक जीवन बीमा निदेशालय

नई दिल्ली-110021, दिनांक 20 अगस्त 1997

सं. 26-82/89-एल आर्डी—राष्ट्रपति एतद्वारा यह निदेश व्रत है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए बीमों की अधिकतम सीमा 10,000 रु. (दस हजार रुपये केवल) की मौजूदा सीमा, जैसा कि हाकवर बीमा विधि नियमावली के नियम 3 के नोट 2 में निर्धारित किया गया है, से बढ़ाकर 1,00,000 रु. (एक लाख रुपये केवल) कर दी जाए जोकि नीचे दी गई अन्य शर्तों के अधीन होगी।

2. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए योजना को "शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष योजना" कहा जाए और इसे पीओआइएफ नियमावली के अंतर्गत मौजूदा नियम 3 के नोट 2 के स्थान पर नियम 14(3) के अंतर्गत शामिल किया जाए और नियम 3 के नोट 2 को निकाल दिया जाए।

3. अतएव पीओआइएफ नियमावली को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :—

(क) नियम 3 के नीचे मौजूदा नोट को निकाल दिया जाए।

(ख) मौजूदा नियम 14 (1) और 14 (2) में नियम 14 (3) को निम्नानुसार जोड़ा जाए :—

"14 (3) (क) :—शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का "शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष योजना" के अंतर्गत बीमा किया जाएगा और उन्हें उनकी विकलांगता की सही प्रकृति तथा उसकी सीमा का निर्धारण करने और इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट विशेष चिकित्सा परीक्षण करवाना पड़ेगा। चिकित्सा

रिपोर्ट में विशेष रूप से निम्नलिखित का समावेश होगा :—

- (1) विकलांगता की सीमा निर्धारित करने वाली एक रिपोर्ट (उदाहरण के लिए विकृति/एक अथवा दोनों अंगों का न होना आदि)।
- (2) विकलांगता का कारण अर्थात् जन्मजात अथवा जन्मोपरान्त।
- (3) प्रस्तावक की घोषणा पर विकलांगता का प्रभाव तथा क्या जीवन का खतरा बढ़ रहा है या घट रहा है।

"जहां चिकित्सा प्राधिकारी ने यह घोषित कर दिया है कि विकलांगता के कारण जीवन का खतरा बढ़ रहा है, वहां ऐसे जीवन का बीमा नहीं किया जाएगा और प्रस्ताव खूद कर दिया जाएगा।

"इसके अलावा यदि प्रस्तावक ने चिकित्सा आधार पर पिछले 6 माह में एक साथ 6 दिन से अधिक का अवकाश लिया है अथवा/तथा पिछले 2 वर्ष के दौरान उसका कोई आपरेशन हुआ है या वह किसी भी कारण से अस्पताल में भर्ती रहा है तो ऐसे व्यक्ति का बीमा नहीं किया जाएगा और बीमा-प्रस्ताव खूद कर दिया जाएगा।

"14 (3) (ख) : निम्नलिखित में से किसी एक विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति "विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष योजना" के अंतर्गत बीमा के लिए पात्र माना जाएगा :

- (1) नेत्रहीनता
- (2) बहुरापन
- (3) गूंगापन
- (4) आर्थोपीडिक विकलांगता
- (5) बीनापन
- (6) कूबड़ापन

(7) अंगभंग

(8) पीलियों के कारण लकवा या बुरबलता या विकृति

(9) गैर-तंत्रिका संबंधी मूल की कोई अन्य विकृति

“14 (3) (ग) : इस योजना के अंतर्गत की गई पालिसियों के संबंध में प्रीमियम निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा :—

द्वेय मासिक प्रीमियम

(क) जन्मजात

नैत्रहीनता/बहरापन/
गूंगापन/एक अंग
की आर्धपीडित विकलांगता
एक अंग
न होना/बौनापन/कुबड़ापन

सामान्य तालिकाबद्ध
प्रीमियम

4. ये संशोधन 1-9-1997 से प्रभावी होंगे।

कर्नल कमलेश्वर प्रसाद
उप महाप्रबंधक

(ख) गैर-जन्मजात

नैत्रहीनता/बहरापन/
एक अंग की आर्ध-
पीडित विकलांगता/
एक अंग का न होना

“X” आयु वाले से
संबंधित तालिका के
अनुसार प्रीमियम,
आयु पर लागू
($X + 3$)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 मिनम्बर 1997

संकल्प

(ग) जन्मजात/गैर जन्मजात

दोनों अंगों में आर्ध-
पीडित विकलांगता,
दोनों अंग न होना
(मंदबुद्धि व्यक्ति
जिनकी मेंटल आयु 14
वर्ष या अधिक है)
पीलियों के कारण
बुरबलता या विकृति
या लकवा अथवा गैर-
जन्मजात मूल की अन्य
कोई विकृति।

“X” आयु वाले से
संबंधित तालिका के
अनुसार प्रीमियम,
आयु पर लागू
($X + 5$)

एफ. सं. 13-9/94-बी. एन.-4—इम मंत्रालय के दि.
30-08-1995 और दिनांक 31-12-1996 के समसंख्य
संकल्प के अनुसरण में भारत सरकार ने जिला प्राथमिक शिक्षा
कार्यक्रम (डी. पी. ई. पी.) मिशन के सामान्य परिषद में
निम्नलिखित संसद सदस्यों को नामित करने का निर्णय लिया
है :—

1. कुमारी ममता बनर्जी
संसद सदस्य, लोक सभा।
2. डा. के. पी. रामलिंगम
संसद सदस्य, लोक सभा।
3. डा. बी. बी. दत्ता
संसद सदस्य, राज्य सभा।

उपयुक्त सदस्यों का कार्यकाल संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा
उन्हें नामित किए जाने की तिथियों से दो वर्षों तक होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि डी. पी. ई. पी.
मिशन की सामान्य परिषद के अध्यक्ष और सभी सदस्यों को भेज
दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना हेतु संकल्प
को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आर. एस. पाण्डेय
संयुक्त सचिव

“14 (3) (घ) : पालिसी की परिवर्तता की तारीख
से पूर्व बीमादार की मृत्यु के कारण पालिसी के द्वारा
दावे का रूप लेने की स्थिति में, नामिती या कानूनी
वारिस को दिये धनराशि, जैसा भी मामला हो,
निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी :—

(क) यदि बीमादार की मृत्यु पालिसी की स्वीकृति
की तारीख से एक वर्ष पूर्ण होने से पूर्व हो जाती
जाती है तो बीमित राशि का केवल 35 प्रतिशत
और उसका ब्याज ही दिये होंगे।

(ख) यदि बीमादार की मृत्यु पालिसी की स्वीकृति
की तारीख के दो वर्ष पूर्ण होने से पूर्व, किन्तु
एक वर्ष पूर्ण होने से पूर्व नहीं, हो जाती है
तो बीमित राशि का केवल 60 प्रतिशत अंश
ही ब्याज सहित दिये होंगे।

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त 1997

सं. 8/11/97-द्वि. 1.—विद्युत मंत्रालय के संकल्प सं. 6/2/97-द्वि. का आंशिक रूप में संशोधन करते हुए, ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडीसा लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निबंधक को इंडीसा राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष की जगह पर पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के सदस्य के रूप में नामांकित किया जा सकता है।

अन्य निर्वाचक सदस्य वहीं रहेंगे।

आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त संकल्प बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सरकार सचिवालय, दामोदर घाटी निगम, दूधगिरि परियोजना लि. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, पावरग्रिड कॉर्पोरेशन लि., केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, पूर्वी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार को प्रेषित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जे. बासुदेवन,
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

DIRECTORATE OF POSTAL LIFE INSURANCE
(DEPARTMENT OF POST)

New Delhi-110021, the 20th August 1997

No. 26-82/89-LI.—The President hereby directs that the maximum limit of Insurance for Physically Handicapped persons shall be increased to a maximum sum assured of Rs. 1,00,000/- (Rupees one lakh only) from existing limit of Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand only) as laid down in Note 2 of Rule 3 of Post Office Insurance Fund Rules subject to various other conditions detailed hereunder.

2. The scheme for Physically Handicapped persons shall be called 'Special Scheme for Physically Handicapped' and shall be included as Rule 14(3) under the POIF Rules instead of present Note 2 of Rule 3 of Post Office Insurance Fund Rules which shall stand deleted.

3. Consequently, the POIF Rules shall be amended as follows :

(a) Existing Note 2 below Rule 3 shall be deleted.

(b) Rule 14(3) shall be added to existing Rule 14(1) and Rule 14(2) as follows :

"14(3) (a) : Physically Handicapped persons shall be insured under the 'Special Scheme for Physically Handicapped' and shall have to undergo a special medical examination by the medical Authorities specified for the purpose in order to determine the exact nature and extent of their handicap and its bearing on the life being insured. The medical report shall include in particular :

(i) A report quantifying the extent of handicap (for example, deformity/loss of one limb, both limbs, etc).

(ii) Cause of handicap, i.e., congenital or post-congenital.

(iii) The effects of the handicap on longevity of the proposer and whether the life risk is increasing or decreasing.

"Provided that where such Medical Authority has declared that the life risk is increasing on account of the handicap, such life shall not be insured and the proposal shall be rejected.

"Provided further that if the proposer has taken leave on medical grounds for more than six days at a stretch in the last six months or/and has undergone any operation or hospitalisation for any reason whatsoever during the last two years, such life shall not be insured and the proposal shall be rejected.

"14(3)(b) : Persons suffering from any of the following handicaps shall be eligible to be considered for Insurance under special scheme for 'Handicapped people' :

- (i) Blindness
- (ii) Deafness
- (iii) Dumbness
- (iv) Orthopaedic handicap
- (v) Midgets
- (vi) Hunchbacks
- (vii) Loss of limbs
- (viii) Paralysis or weakness or deformity due to Polio.
- (ix) Any other deformity due to non-neurological origin.

"14(3)(c) : Premium in respect of policies taken under the scheme will be determined as under :

Monthly premium Payable

(a) Congenital

Blindness/deafness/ dumbness Orthopaedic handicap of one limb/ loss of one limb/Mid- gets/Hunchback.	Normal tabular premium
--	------------------------

(b) Non-Congenital

Blindness/deafness/ orthopaedic handicap of one limb/loss of one limb.	premium applicable to age (X+3) as per relevant table for life aged 'X'.
---	--

(c) Congenital/Non-Congenital

Orthopaedic handicap of both limbs, loss of both Limbs (Mentally retarded having mental age of 14 and above), weakness or deformity or paralysis due to polio or any other de- formity of non-neuro- logical origin.	Premium applicable to age (X+5) as per relevant table for life-aged 'X'.
---	--

"14(3)(d) : In the event of the policy becoming a claim on account of death of the insured before the date of maturity, the amount payable to the nominee or the legal heir, as the case may be, shall be determined as follows :

- (a) In case the death of the insured takes place before the completion of one year from the date of acceptance of the policy, only thirty five percent of the sum assured and the accrued bonus shall be payable.
- (b) In case the death of the insured takes place before the completion of two years but not before the completion of one year from the date of acceptance of the policy, only sixty percent of the sum assured and the accrued bonus shall be payable.
- (c) In case the death of the insured takes place before the completion of three years but not before the completion of two years from the date of acceptance of the policy, only ninety percent of the sum assured and accrued bonus shall be payable.
- (d) In case the death of the insured takes place after the completion of three years, full sum assured along with accrued bonus thereon shall be payable."

4. These amendments shall come into force with effect from 1-9-97.

Col. KAMLESHWAR PRASAD,
Dy. General Manager

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 8th September 1997

RESOLUTION

F. No. 13-9/94-PN.IV.—In pursuance of this Ministry's Resolution of even number dated 30-08-1995 and 31-12-1996, Government of India have decided to nominate the following Members of Parliament on the General Council of the District Primary Education Programme (DPEP) Mission :

1. Kumari Mamta Banerjee,
Member of Parliament, Lok Sabha.
2. Dr. K. P. Ramalingam,
Member of Parliament, Lok Sabha.
3. Dr. B. B. Dutta,
Member of Parliament, Rajya Sabha.

The tenure of office of the above members would be two years from the dates of their nominations by the Ministry of Parliamentary Affairs.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and all members of the General Council of the DPEP Mission.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. S. PANDEY, Jt. Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 29th August 1997

No. 8/11/97-Trans.—In partial modification of this Ministry of Power Resolution No. 6/2/97-Trans, the Chairman and Managing Director, Grid Corporation of Orissa Ltd. may be nominated as member of Eastern Regional Electricity Board in place of the Chairman, Orissa State Electricity Board.

The other constituent member's remain the same.

ORDER

Ordered that the above Resolution be communicated to the Government and State Electricity Boards of Bihar, Orissa, West Bengal and State Govt. Sikkim, Damodar Valley Corporation, Durgapur Projects Ltd., National Thermal Power Corporation, National Hydroelectric Power Corpn. Powergrid Corporation Ltd., Central Electricity Authority, Eastern Regional Electricity Board, All Ministries of Govt. of India. The Prime Minister's Office, the Secretary to the President, the Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for General information.

J. VASUDEVAN Jt. Secy.